[Shri Charanjit Chanana]

would not appreciate the rising value of the capital. In fact, we have always been talking against inflation, which we do to-day also. Because of the fact that this very unit has started showing signs of being cured, we may be reaching the second stage. When the unit is already losing, you do not want it to sell things at lower than the cost of production. The cost of production is high and that is a relative thing, as far as the market costs are concerned. (*Interruptions*) This Act, unfortunately, cannot give you subsidy. Subsidies are to be fed into the sick units, and they are never to be subsidies alone. They should be indentives which strive to cure the unit of sickness. This particular amendment relates to a very specific thing, where we are trying to ease the situation, to cure the liabilities to the extent, again, of public funds—the State Bank of India is, in fact, as much yours as anybody else's in the country.

I will appreciate it if, in view of this, the Bill is considered.

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill to amend the Hindustan Tractors Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1978, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: Now we take up clause-by-clause consideration of the Bill. The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. SPEAKER: Now the Minister.

SHRI CHARANJIT CHANANA: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

17.19 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE.

DECLARATION OF TWO DISTRICTS OF TRIPURA AS DISTURBED AREAS

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मै अविलम्बनीय महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में वक्तव्य दें :—

"बड़े पैमाने पर हुई हिंसक घटनाओं में भारी संख्या में लोगों के हताहत होने के कारण त्रिपुरा के दो जिलों को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करने का समाचार ।"

गृह मंत्री (श्री ज्ञैल सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी माननीय सदस्यों को मालूम है, 7 जून से त्रिपुरा के अन्दर गम्भीर हिंसा की घटनायें होने के कारण मैं अपने साथियो, वाणिज्य मंत्री और उपमंत्री, सिविल सप्लाईज और पुनर्वास, के साथ 11 जून को त्रिपुरा गया था । राज्य सरकार के पास प्राप्त सूचना के अनुसार 315 आदमियों की जानें गई, सैकड़ों लोग घायल हुए 100 से ऊपर गांवों में घरों को जलाया गया और एक लाख से अधिक व्यक्ति बेघर हो गये और उन्हें सहायता कैम्पों में ठहराया गया है । कुछ लोगों ने चिन्ता व्यक्त की है कि जान और माल का नुकसान इससे भी ज्यादा हुआ है ।

मैं ने तथा मेरे साथी मंत्रियों ने उन स्थानों का सर्वेक्षण भी किया, जहां हिंसक घटायें हुई थी और यह देखा कि बहुत से गांवों में खाली

घरों में उस समय तक भी आग जल रही थी। हम कुछ सहायता कैम्पों और अगरतल्ला हास्पिटल में भी गये, जहां लगभग 500 घायलों को भर्ती किया गया है, और उन दुखी लोगों की करुणापूर्ण और दिल दहला देने वाली कथाओं को सुना। हम ने उन के प्रति सहानुभूति दिखलायी और बतलाया कि यह सरकार इस के बारे में बहुत चिन्तित है और आश्वासन दिया कि सरकार अपराधियों को दण्ड देने के लिए पूरी कोशिश करेगी तथा हिंसात्मक घटनाओं के शिकार व्यक्तियों की हर प्रकार की सहायता देगी। अगरतल्ला में ठहरने के दौरान हम से विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि-मंडल भी मिले।

उपरोक्त हिंसात्मक घटनाओं के बारे में कोई अन्तिम निर्णय अभी इस समय नहीं लिया जा सकता लेकिन यह साफ है कि विभिन्न ग्रुपों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। इस का एक कारण निश्चित रूप से आसाम के आन्दोलन का प्रभाव भी है। ऐसा लगता है कि हिंसक और समाज विरोधी तत्वों ने स्थिति का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की।

केन्द्रीय सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया और सहायता शुरू कर दी। सेना और पैरा-मिलिट्री फार्सेज तुरन्त भेज दी गई हैं। उन की टुकड़ियों को हवाई जहाज से भेजा गया और वह भीतरी भागों में तैनात कर दी गई हैं। राज्य सरकार लगभग 715 व्यक्तियों को हिरासत में ले चुकी है लेकिन स्थिति अभी तनावपूर्ण दिखाई देती है और इस पर कड़ी नजर रखा जाना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं इस सदन की सहानुभूति उन सब परिवारों को पहुंचाना चाहता हूं जिन का इन हिंसात्मक घटनाओं के कारण जान व माल का नुकसान हुआ है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री के बयान को हम लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है। त्रिपुरा में जो कुछ हुआ है वह असाधारण है। अगर उसे नरमेध की संज्ञा दी जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्वतंत्र भारत में इतने बड़े पैमाने पर लोगों का मारा जाना और उन का घरों से निकाला जाना—और दुख की बात यह है कि घरों से जो लोग निकाले गए हैं उन में बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो एक बार उजड़ कर हमारे देश में फिर से बसने के लिए आए थे, आज फिर वे अपने ही देश में शरणार्थी हो गए हैं।

गृह मंत्री महोदय ने सारे सदन की ओर से मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है, दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की है और उन के परिवार वालों के साथ सहानुभूति प्रकट की है, मैं उस में अपनी आवाज मिलाना चाहता हूं।

इतने बड़े पैमाने पर उपद्रव बड़ी तैयारी बाद ही हो सकते हैं। यह तैयारी कब से चल रही थी? उपद्रवकारियों के हाथ में हथियार कहां से आए? विदेशी हथियार उन्हें प्राप्त हो रहे हैं इस तरह के समाचार छपे हैं, उन में कहां तक सचाई है?

पहले भी इस आशय की खबर मिली थी कि त्रिपुरा में एक त्रिपुर-सेना बनी है जो त्रिपुरा को मुक्त करने की बात करती है और सशस्त्र क्रान्ति के माध्यम से इस प्रकार से त्रिपुरा का पृथक्करण करना चाहती है। एक और मिजो नेशनल फ्रंट से इनके गठबन्धन की बात कही जाती है, दूसरे, यह कहा जाता है कि इन के लोग चटगांव हिल-ट्रैक्ट्स में जा कर सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

मंत्री जी ने आसाम के आन्दोलन को भी इस में जोड़ दिया है और उन्होंने कहा कि एक कारण यह है। हो सकता है कि आसाम के आन्दोलन की प्रतिक्रिया वहां हुई हो, मगर मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे कि त्रिपुरा का मामला वर्षों से बिगड़ रहा है। मैं पुराने अखबारों की कतरनें देख रहा था। 9 मई, 1968 के इंडियन एक्सप्रेस का एक लेख मेरे सामने है जिसका एक अंश मैं पढ़ना चाहता हूं—मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा :

"Dark clouds portending imminent storm are gathering on the political horizon of Tripura: unawaited influx of Bengali Hindus from East Pakistan, consequent disturbance of the demographic equilibrium and growing pressure on land, acute food shortage, increasing unemployment, complete neglect of the backward and hill areas, shocking apathy of an indolent but all powerful bureaucracy have created an explosive situation in this highly vulnerable region."

इसके बाद त्रिपुरा में कुछ राजनीतिक कदम उठाए गए जिन के अन्तर्गत लोगों को अपने प्रतिनिधियों द्वारा अपना शासन चलाने का मौका मिला लेकिन वहां के ट्राइबल्स को ऐसा लगा कि उनका अस्तित्व खतरे में है, शायद उनकी पहचान भी समाप्त हो जायेगी।

क्या यह सच है कि त्रिपुरा में जो वर्तमान सरकार है वह चाहती थी कि ट्राइबल एरियाज में आटोनामस डिस्ट्रिक्ट्स बने, उनकी कौंसिल हो और वह कौंसिल अपने जिले का शासन सम्हाले? इस बारे में एक ऐक्ट भी बना, राष्ट्रपति महोदय ने उसको अपनी स्वीकृति दे दी लेकिन वह अमल में नहीं आ सका क्योंकि शायद वह मामला हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

मैं जानना चाहता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से सारे सवाल को हल करने के लिए इससे पहले कोई कदम क्यों नहीं उठाये गए ?

अभी तो कानून और व्यवस्था बनाए रखना पहला कर्तव्य है। इसलिए जिन्होंने हथियार इकट्ठे किए, उनका उपयोग किया और जो बड़े पैमाने पर हत्याकाण्ड के दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ेगी लेकिन यह आवश्यक में कि केन्द्र और त्रिपुरा की सरकार के बीच में पूरा तालमेल हो। इसमें राजनीतिक स्वार्थों को बीच में आने देने की छूट नहीं होनी चाहिए। कभी-कभी यह मांग आती है, कांग्रेस (आई) के मित्रों से कि त्रिपुरा सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए क्योंकि वहां की सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सफल नहीं हुई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा क्या इस तरह का विचार सरकार के दिमाग में कहीं है ?

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : अगर नरमेध चलता रहे तो ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर यह चलना रहे तो केन्द्र और प्रदेश की सरकारें मिलकर कदम उठायें। प्रदेश सरकार को समाप्त करने से सारी परिस्थिति और बिगड़ जायेगी और उसको सुधारने की संभावना नहीं रहेगी, या फिर आप कहें कि प्रदेश की सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद नहीं दे रही है, वह बाधक बन रही है इसलिये हटाना जरूरी है।

दूसरी बात यह है कि मंत्री महोदय अपनी यात्रा के दौरान—उनकी यात्रा बहुत छोटी थी, मैं मानता हूं, वे तत्काल गए यह बहुत अच्छा हुआ—वाणिज्य मंत्री को अपने साथ क्यों ले गए, यह बात समझ में नहीं आई। उनके अपने कारण होंगे, मैं उनमें जाना नहीं चाहता। लेकिन आर्थिक दृष्टि से त्रिपुरा की उपेक्षा हुई है। वर्तमान परिस्थिति में आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए कोई लम्बे-चौड़े कार्यक्रम नहीं बन सकते और न चर्चा हो सकती है। हो सकता है कि अपनी सहायता के लिए गृह मंत्री उन्हें ले गए हों कि बंगला भाषियों से बात करने में श्री प्रणव मुकर्जी उनकी सहायता कर सकें। गृह मंत्री जी ने शायद इस सम्बन्ध में उनकी सहायता प्राप्त की हो। त्रिपुरा समस्या के दो पहलू हैं, एक तो हत्याकाण्ड बन्द करना, हिंसा की समाप्ति और शांति की स्थापना और दूसरे ट्राइबल्स में यह विश्वास पैदा करना कि भले ही बड़ी संख्या में लोग आये हैं, बसे हैं, जिससे उनकी आबादी घट गई है फिर भी उनके हितों की, उनके जीवन पद्धति की रक्षा की जायेगी। परन्तु इस तरह का कोई भी वक्तव्य गृह मंत्री जी का मैंने समाचार-पत्रों में छपा हुआ नहीं देखा है। एक बयान में आपने यह कहा है कि त्रिपुरा की समस्या आर्थिक नहीं है। लेकिन त्रिपुरा की समस्या आर्थिक भी है और ट्राइबल्स द्वारा अपने अस्तित्व की रक्षा करना भी है। मैंने प्रारम्भ में कहा था कि इतना बड़ा नरमेध बड़ी तैयारी के बाद होना चाहिए तो सरकार की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी ? त्रिपुरा के मुख्य मंत्री दिल्ली में आए हुए थे। (व्यवधान) राज्यों की सी० आई० डी० होती है, उसको हम पहचान सकते हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी ? केन्द्रीय सरकार के पास इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी थी या नहीं ? क्या उसे आभास था कि इतने बड़े पैमाने पर हत्याकाण्ड की तैयारी हो रही है ? मंत्री जी ने अपने बयान में कहा है—मिलिटेंट ऐंड एंटी सोशल एलिमेन्ट्स—तो यह कौन से तत्व हैं ? (व्यवधान) कांग्रेस के एक सदस्य कह रहे हैं आर०एस०एस० वाले लेकिन मुझे खुशी है कि आज जब अफगानिस्तान के सम्बन्ध में चर्चा हो रही थी तो विदेश मंत्री ने आर०एस०एस० को अफगानिस्तान की समस्या के लिए दोषी नहीं ठहराया ! त्रिपुरा में ये मिलिटेंट कौन हैं, इनका किन के साथ संबंध है ? बाहर से रुपया आ रहा है और हथियार आ रहे हैं, क्या उसकी रोकथाम की कोशिश की गई है और मंत्री महोदय क्या समझते है कि कब तक सारी परिस्थिति पर काबू प्राप्त कर लिया जायेगा ?

श्री जैल सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय वाजपेयी जी ने कई बातें कही हैं। आखिर में तो वह सवालों पर ही आये, लेकिन उन्होंने कुछ तामीरी बातें भी कहीं हैं, उनके लिये मैं उनका मशकूर हूं।

उन्होंने पूछा कि ये हथियार कहां से आये ? हथियार जिनका नाजायज इस्तेमाल हुआ है, वे वहीं बनाये गये थे। जो अब तक की रिपोर्ट है उसके मुताबिक कुछ ऐसे असलाह इस्तेमाल हुये हैं जिनके लाइसेंस सरकार ने दिये थे, वही लाइसेंस के असलाह इस्तेमाल हुए हैं। विदेशी बने हुये या विदेश के शस्त्र पकड़ गये हैं—वहां की सरकार ने हम को ऐसा नहीं बताया है और हमारे पास ऐसी कोई बात नहीं पहुची है।

एक बात वाजपेयी जी ने कही कि जो लोग पहले उजड़ कर आये थे, वे फिर उजाड़े गये—यह बात सारी की सारी सही नहीं है। बहुत से तो ऐसे लोग घरों से निकाले गये जो सदियों से वहीं बसते थे। वे किसी भी जमाने में किसी दूसरी प्रांत में भी नहीं थे, वहीं रहते थ और मैंने वहां एक छोटा सा कैम्प भी देखा जो ट्राइबल्ज का था। अब देखना यह है कि जो नफरत की भावना का आज वहां प्रचार है, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, ट्राइबल्ज नान-ट्राइबल्ज का जो प्रचार है, उस को रोका नहीं गया और काफी मुद्दत से वह प्रचार हो रहा था जिसका असर लाजमी तौर पर होना था।

आप यह मानेंगे कि तैयारी पहले की गई होगी, मैं भी आशंका प्रकट करता हूं कि तैयारी पहले

की गई होगी, लेकिन वाजपेयी जी आप मेरे साथ इत्तिफाक करेंगे कि त्रिपुरा की सरकार हो या कोई और सरकार हो, कांग्रेस (आई) की सरकार न हो, तब भी सेंन्ट्रल गवर्नमेंट जो है, वह भेदभाव नहीं रखती है । उनके साथ पूरे सहयोग से चलती है और हमको ऐसी कोई शिकायत भी नहीं है कि त्रिपुरा की सरकार ने सेन्ट्रल गवर्नमेंट के साथ या उनकी जो आज्ञा का पालन करना जरूरी है उससे या सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सबजैक्ट में, कोई दखल दिया हो । इसलिये यह बात कहना वैसे तो यथार्थ है, इन-प्रिन्सिपल अच्छी बात है कि मिलजुल कर दोनों को काम करना चाहिये और ऐसा हो भी रहा है, इसमें आप को कोई चिन्ता प्रकट नहीं करनी चाहिये । मगर आप यह भी मानेंगे कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट, वहां पर ड्यूली इलेक्टेड लोगों की सरकार है, वहां के अन्दरुनी मामलात में, छोटी-मोटी बातों में, मदाखलत करना मुनासिब नहीं समझती है । जो स्टेट का सबजैक्ट है, उसमें बगैर स्टेट की डिमांड के सेन्ट्रल गवर्नमेंट मदाखलत करे या ऐसे समय में की जा सकती है जैसा कि इन दिनों में त्रिपुरा में वाक्या हुआ है, उसके लिये भी आप यह कह रह हैं कि मदाखलत न करे । आपने कांग्रेस (आई) के किसी लीडर का कोई स्टेटमेंट देख लिया होगा, लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आई । हमारे किसी कांग्रेस (आई) के नेता ने यह बात नहीं कही कि चूंकि त्रिपुरा की सरकार वहां के अमन और शांति में फेल हो गई है, इसलिये वहां की असेम्बली को डिजाल्व कर दिया जाय । ऐसी बात हमने सोची भी नहीं है और हमारे दिमाग में भी नही हैं । हम ने तो जितनी मदद उनको चाहिये, उतनी मदद दे दी है, और भी मदद देने के लिए तैयार हैं । लेकिन इस बात का ख्याल कि कितनी तैयारी उन्होंने की है, उनको करनी चाहिये, हमारी सेन्ट्रल इंटेलिजैंस को भी करनी चाहिये । लेकिन हमारी सेन्ट्रल इंटेलिजेंस ने जो वक्तन-फवक्तन इत्तिला दी, उसके बारे में हमने तमाम हिन्दुस्तान के गवर्नरों और मुख्य मंत्रियों को लिखा था । उसमें कुछ थोड़ी सी स्टेटमें में नफरत की भावना और नफ रत के प्रचार की बात थी, लेकिन हमने सबको लिखा कि इस बात पर कड़ी निगाह रखी जाय, क्योंकि कास्टइज्म, रीजनलिज्म, लिंग्वलिज्म, ये सब चीजें हमको एक दूसरे का दुश्मन बना सकती हैं, इनको रोकने के लिये स्पेशल इंतजाम करना चाहिये, इन पर पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिये । साथ ही साथ हमने यह भी लिखा—शायद आपके पास मेरा वह पत्र और एक पत्र प्रधान मंत्री जी का भी गया हो—उनमें इन सारी बातों पर ध्यान रखने के लिये कहा गया था । लेकिन इसमें किसी को मजबूर करने का प्रश्न नहीं है और आप भी किसी को मजबूर करने के हक में नहीं हैं । आप की भी यह राय है कि हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलजुल कर इस मामले का हल निकालें ताकि आइंदा के लिये कोई ऐसा वाक्या न हो ।

आपने पूछा है कि मिलिटेंट ग्रुप्स कौन से हैं, कहां से आते हैं और क्या विदेशी शक्तियों ने कोई दखल दिया है या नहीं दिया है । इसके प्रति मेरा तो यह विश्वास है कि जहां भी डिस्टरबेंस हो, झगड़ा हो, एक दूसरे के खिलाफ भाई का भाई गला काटने को तैयार हो तो दुनिया में कुछ ताकत ऐसी हैं जो ऐसे हालात में खुश होती हैं और कोशिश करती हैं कि उसमें दखल दिया जाय ताकि उस मामले को बढ़ाया जाय और उस बढ़ावे में किसी न किसी ताकत का हाथ हो, सकता है । उस को आर्गेनाइज करने वाली ताकतें, जैसा मैंने आसाम के प्रति कहा था, परसों, वाजपेयी जी, आप हाउस में नहीं थे, मैंने दरख्वास्त की थी, भले ही आपने नेकनीयती से वहां के नौजवानों को आर्गेनाइज किया हो, जो सात हजार के करीब थे, लेकिन इसके फलस्वरूप कोई अच्छी बात नहीं निकली और आज वह बात उनके हाथ में भी नहीं रही । शायद आपने तो सिर्फ इसलिये आर्गेनाइज करवाया हो या आर० एस० एस० ने इसलिये आर्गेनाइज किया हो कि धार्मिक तौर पर भारत की संस्कृति को मजबूत रखने के लिये, नौजवानों में शिष्टाचार पैदा करनें के लिये—शायद यह सब किया हो, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ ? गैर-हिन्दुओं के मन में नफरत पैदा हुई—यह बुरी बात थी । अब उसको सुधारने के लिये मैं आप से अपील करूंगा, आर० एस० एस० के नेताओं से अपील करूगा । मैं ही नही कहता, आप खुद ही जाकर देख लीजिये कि उसका क्या प्रभाव पड़ा है । इन शक्तियों के पीछे सहायता देने वाले आर० एस० एस० के वालंटीयर्स हैं या नही है, मैं इस बात को आप पर छोड़ता हूं । लेकिन एक बात को आप मानेंगे, कि जब मिलिटेंट फोर्सेज का जिक्र करते हैं तो उन में आर० एस० एस० भी आती है, जो पैरा-मिलिट्री संस्था की तरह से काम करती है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, त्रिपुरा की बात हो रही है, असम की नहीं ।

श्री जैल सिंह : इस का मतलब है कि आप ने माना, मेरे से इत्तिफाक किया है । इस मे एक कारण यह भी था कि मैंने अपने स्टेटमेंट को बहुत गार्डेड लैंग्वेज में दिया है । मैं नहीं चाहता कि उन बातों को हाईलाइट किया जाय जो बातें वहां होती रहीं हैं, वह कौन सा ग्रप था, कैसे लड़ा, क्यों लड़ा, इन बातों को डिटेल में अगर हम पार्लियामेंट में जायेंगे तो वे हाइलाइट होंगी । हम नहीं चाहते है कि नफरत बढ़े, हम यही चाहते हैं कि उन को तरीके से सुलझाया जाय ।

आप का ख्याल था कि आटोनामस डिस्ट्रिक्ट्स बनाने के लिये कोई बिल आया था—आप दुरुस्त कहते हैं ।

The validity of the Tripura Tribal Area Autonomous District Council Act, 1979 was challenged in the Gauhati High Court.

इस वक्त वह फुल बैंच के सामने गया है, वहां क्या हो रहा है यह तो एक डिटेल की बात है। लेकिन वह अभी अमल में नहीं लाया। मगर मैं इस बात से इत्तिफाक करता हूं कि उस ऐक्ट में भी कुछ भावना जरूर पदा हुई होगी, क्योंकि आटोनामस शब्द से किसी को यह कहना कि मैं आजाद नही हूं, स्वतंत्र नही हूं, मुझे स्वतंत्रता दी जाय, इस से अलहदगी की भावना पैदा होती है। वाजपेयी जी ने भी माना है कि अलेहदगी की भावना भी वहां कुछ काम करती है। आपने यह भी कहा है कि त्रिपुरा को अलेहदा करने के लिये त्रिपुरा की सेना बनी है। मैं इस मामले में आप से इत्तिफाक करता हूं कि इस चीज को राजनीतिक तौर पर नही लेना चाहिये। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा एमेंडमेंट कर लीजिये। आप यह कर दीजिये कि पार्टी के तौर पर नहीं होना चाहिये क्योंकि राजनीतिक तौर पर तो इस को करना ही है, राजनीति के बगैर सुधारा नही जा सकता। हम यहां क्यों आये हैं? राजनीति में ही आये हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा मतलब पार्टी से ही था, पोलीटीकल कांटेक्स्ट में नही था।

श्री खेल सिंह : शुक्रिया। धन्यवाद आप का। मैं यह कहता हूं कि राजनीतिक तौर पर तो इसको करना ही पड़ेगा लेकिन आप यह कह सकते है कि राजनीतिक तौर पर सुधारने के लिये आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक शक्तियो को भी साथ लिया जाय। यह बात तो हो सकती है। यह कह दें कि राजनीति को छोड़ दो तो यह समस्या कैसे हल होगी। यह तो हम को और आप को सबको मिल-जुलकर करना हैं। मेरा ख्याल है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी तो बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं उनको मेरी बातो से तसल्ली हो गई होगी।

SHRI CHINTAMANI JENA (Balasore): I am grateful to the hon. Home Minister for his immediate visit to the spot to see for himself the affected areas. You may be knowing, Sir, that our Home Minister was giving facts about the agitation that is going on there, on day before yesterday while replying on Assam debates. After his enquiry, he has made a statement here and also given a reply to the questions put by Mr. Vajpayee, I want to have a categorical answer from him.

In the Indian Express published yesterday, the 11th June, there is a news item saying:

"The administration has completely collapsed and a state of civil war prevails in the State."

May I know from the hon. Home Minister whether, after his enquiry on the spot, actually the administration has collapsed and a state of civil war is prevailing? If so, what action does the Union Government want to take to strengthen the State Government there or any other action so that peace may be restored there?

There is another news item published in the same newspaper which says:

"Mr. Chakravorty told newsmen in Agartala that there was sufficient reason to suspect the involvement of foreign power' in the current disturbances."

The hon. Minister has also made a similar type of statement to the press while at Tripura that certain foreign powers are behind this. May I know which are the foreign powers which are behind this and creating such disturbances?

There is another news item in the same newspaper which says:

"The Chief Minister, who was persistently questioned on the competence of the state intelligence, said he had repeatedly urged the Centre to strengthen the law and order machinery in view of the 900-km-long border with Bangladesh and the frequent attacks by Mizo underground rebels. But the Centre had not heeded him."

17.44 hrs.

[SHRI SHIVRAJ V. PATIL *in the Chair.*]

In this connection, may I know from the hon. Home Minister when the State Government asked for help and what was the help that was given by the Centre to strengthen the security of the State?

Again the news item says:

"The forces now at the disposal of the State Government were inadequate to deal effectively with the situation."

But from the statement made by our hon. Home Minister, it is clear that the situation is tense there.

In this connection, is the Home Minister satisfied that the situation will not be aggravated and the forces sent there are adequate to control the situation?

Another thing is, it is published today in the newspapers like the *Indian Express* that after the army and the police were sent there some sophisticated arms were recovered after they raided some places. May I know what type of arms are there and what are their numbers and are they foreign-made or country-made? In this connection, I would like to know this: Are there any Mizo rebels who are causing these disturbances? If so, what action is Government going to take against them?

Lastly, after the loss to the human lives, has the Government sanctioned some *ex gratia* grant to those who have lost their lives and those who were rendered homeless? If so, what is the amount and has the Home Minister discussed the matter with the State Government on this issue?

When the situation is tense there, may I urge upon the Home Minister that a Committee be formed in this House—it may be called as a Peace Committee or something like that—to go to the spot and see that the situation is diffused?

On these questions I want a categorical reply from the Home Minister.

श्री ज़ैल सिंह : आनरेबल मेम्बर साहेबान ने कुछ तो बातें वही पूछी हैं जो श्री वाजपेयी जी ने पूछी थीं। उनका तो जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। लेकिन उनका जो यह पूछना है कि वहां की जो सिचुएशन है, जिसके मुतल्लिक मैंने कहा कि टेंस है, उसके लिये जो फोर्सिज भेजी गयी हैं क्या उनसे हमको तसल्ली है या नहीं, इसके बारे में मैं यह बता देना चाहता हूं कि हम और फोर्सिज वहां भेजना चाहते है क्योंकि वहां की जो सिचुएशन है वह बिल्कुल शांत नही हुई है। बी० एस० एफ० आदि की चार पलटनें वहां भेजी गयी है। कुछ मिलट्री को भी कहा है कि वे भी कुछ अलर्ट रहें।

आपने एक्स ग्रेशिया ग्रांट उनको कितनी दी गयी है इसके बारे में भी पूछा। यह तो मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि यह छोटी सी बात तो है नहीं। यह बहुत बड़ा मामला है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी आती है। वह कितनी ग्रांट देती है इसका भी सवाल है। लेकिन हमनें यह भरोसा उनको दिलाया है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल कर उन मुसीबतजुदा लोगों की पूरी पूरी और ज्यादा से ज्यादा सहायता करें।

SHRI CHINTAMANI JENA: What about foreign powers and Mizo rebels?

श्री ज़ैल सिंह : फारेन पावर की बात मेम्बर साहिबान कह रहे हैं। अगर आनरेबिल मेम्बर यह बात कहें तो मैं उसे कांट्रडिक्ट कसे करूं।

SHRI EDUARDO FALEIRO (Mormugao): In his otherwise comprehensive statement, the hon. Home Minister has overlooked one important aspect to which he will have to address himself if he is ever to attempt a long-term solution of this issue, and that aspect relates to the causes of the present agitation. In para 4, the hon. Home Minister says only this much:

"It is too early to come to a conclusive finding regarding the causes of the outrage."

May I say that the causes of the outrage or outrages are there for everyone to see, and the causes are the genuine grievances, the genuine fears of the tribal people who see themselves being swamped and liquidated step by step in the country which was their own.

If you look at the demographic figures from time to time, you will see that the tribal people who constituted practically one hundred per

[Shri Eduardo Faleiro]

cent of the population at one time were only 48.57 per cent according to the 1941 census. This percentage was reduced to 30.88 per cent in the 1951 census, and in the latest census of 1971, it has been further reduced to 28.95 per cent. As compared to this, the proportion of others to the total population has been increasing. In 1941 it was 51.43 per cent; in 1951 it was 69.91 per cent, and in 1971 it was 71.05 per cent. Political leadership and economic opportunities being denied and the demographic liquidation are the causes of this agitation. Mr. Nripen Chakravarti, the Chief Minister of that State, himself came from West Bengal some years ago. There is hardly any Minister in the Tripura Government who is a tribal. (*Interruptions*).

You tell me how many there are out of the total.

It is my submission that the 19 reserved seats for the tribals has been further reduced to 17. Among the Members of Parliament, one came from Tripura only ten years ago, and there is not a single tribal Member of Parliament from there. (*Interruptions*).

He has referred to the Tripura Upajati Samiti, but he has not referred to another extremist organisation which is working there, and it is the Amra Bengali. The Marxist Left-Front Government has lost the confidence of the Tribals there. It has been the Marxist politicians who have been propagating the idea of a Greater Bengal which will consist of East Bengal, West Bengal, Tripura and Cachar and Silchar Districts of Assam.

MR. CHAIRMAN: I will request the hon. Member not to make a statement, but to ask a question.

SHRI EDUARDO FALEIRO: It has been the practice of this House in the past, and it is the practice today also in this very calling attention, to make some prefatory remarks, and it is that sort of remarks that I am making. I will conclude these remarks by saying that the Left-Front Government which is in power there has lost the confidence of the Tribals and cannot solve the problem.

Belonia, which is one of the areas where several important and most tragic incidents have taken place in May this year and thereafter, is manned entirely by a platoon of police constituted almost exclusively by Marxist cadre which was created about three years ago, after the Left-Front Government came to power.

In view of the obvious fact as of today that the State Government is unable to control the situation, in view of the fact that the Tribals, who constitute a major section, an interested section of the people there, do not have confidence in the Government, will the hon. Home Minister after looking at the breakdown of law and order and the carnage that has taken place, the gravest ever since India became independent, take over the administration and impose President's rule? (*Interruptions*) This is the only obvious course left to the Government of India. Let the Home Minister tell us whether he does not intend to impose President's rule there and if so, the reasons for the same. There are precedents for imposing President's rule. May I also request the Home Minister that after imposing the President's rule, he may attempt a negotiated settlement with all the interested parties so as to find a long term and permanent solution to the problem.

श्री जैल सिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने इस बात पर फिर जोर दिया है कि वहां के आन्दोलन के क्या कारण है, वह बतायें । मैंने पहले ही अपने स्टेटमैंट में इसका जवाब दिया था कि अभी कोई नतीजा निकालना अच्छा नहीं होगा और जो बातें उन्होंने कही हैं, मैं उन्ही को एवायड करना चाहता था ।

जो ट्रायबल और नान-ट्रायबल का आपस में एक दूसरे के खिलाफ प्रचार होता है, उससे ज्यादा नफरत पैदा हुई है, कारण यह भी एक है, मैं इस

से इत्तफाक करता हूं, लेकिन जो उनका ख्याल है कि ट्राइबल लोगों को डर है कि उनकी संख्या कम हो जायेगी और कम होती गई है, और दूसरे लोगों की संख्या बढ़ गई है, इस बात का डर है, जहां तक सेन्ट्रल गवर्नमेंट का सवाल है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट किसी भी ट्राइबल को, किसी भी एरिये के लोगों को उनके वे-आफ लाइफ को, जो उनका ट्रेडीशनल वे आफ लाइफ है, उसको डिस्टर्ब नहीं होने देगी। उनके कल्चर, उनके रवायात और रस्मोरिवाज को हर तरह से प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन एक बात जरूर माननी पड़ेगी कि भारत में बसने वाले लोग किसी भी प्रांत के सिटीजन हों, उनको किसी भी प्रांत में रहने का हक अगर हम नहीं देते तो भारत की एकता टूट जायेगी। इसलिये हम उनका सम्मान भी करते हैं, आदर भी करते हैं। ट्रायबल्स की जो जरूरतें हैं,उसका अध्ययन करने के लिये मैं चाहूगा कि मेम्बर सहबान उसका अध्ययन करें, सरकार की यह पूरी मंशा है कि उनके रस्मो-रिवाज उनका रहन सहन और उनकी ट्रेडीशनल लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिये आवश्यक कदम उठाये और यह सरकार कर रही है। इसके साथ ही साथ ट्राइमेंबल से भी यह प्रार्थना करूंगा कि वह दूसरे प्रांतों ह रहें, वहां काम करें यहां सैंटर में काम करें ताकि हमारे सब लोगों में एक नेशनल भावना पैदा हो।

दूसरा जो उनका ख्याल है कि ट्राइबल का मंत्री कोई नहीं है, तो ट्राइबल का एक मंत्री है एजूकेशन मिनिस्टर। उस एजूकेशन मिनिस्टर के प्रति भी और सी० एम० के प्रति भी थोड़ा कहा गया, लेकिन यह अच्छी बात नहीं हैं। वहां की सरकार सी० पी० एम० की हो या और किसी की हो, ऐसे नाजुक समय में सरकार को कमजोर करना ठीक नहीं। (व्यवधान) वहां के लोगों की इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको हम तोडने की कोशिश करें, यह ठीक नहीं।

गुप्ता जी आप बैठे-बैठे बोलते हैं, आप क्या चाहते हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : (बसीरहा) मैं कहता हूं कि इस मामले में पार्टीबाजी नहीं करनी चाहिये, जो आपके मैम्बर कर रहे हैं।

श्री जैल सिंह : वह आपको कह रह हैं आपको नहीं करनी चाहिये। वे भी यही बात कहते है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जो यहां बोल रहे हैं, वही वहां कर रह हैं।

सभापति महोदय : सदन का समय 6 बजे खत्म होता है। रेप्लाई देनें के लिये समय बढ़ा दिया जाता है।

18.00 hrs.

श्री जैल सिंह : मैं यही समाप्त कर देता हूं। मैंने बताया है कि ट्राइब का एक मंत्री भी है और रिजर्वड सीटें भी हैं। मुझे जो इत्तिला मिली है, उसके अनुसार मैं कह रहा हूं। 16 रिजर्वड सीटे हैं लेकिन ट्राइबल के 18 मैम्बर्स हैं। दो मैम्बर जनरल सीटों पर जीत कर आये हैं। उनका सरकार में पूरा हिस्सा है। यह बात सह है कि मुख्य मंत्री ट्राइबलस में से नहीं हैं। दूसरे जो बंगाली लोग उनमें से आए हुये हैं।

मैं मेम्बर साहेबान से इतनी प्रार्थना जरूरी करूंगा कि अगर कोई आदमी चीनी, चीनी कहता रहे, तो उसका मुंह मीठा नहीं होता है, जब तक कि वह लाकर न दी जाय। एक दूसरे को यह कहने का कोई फायदा नहीं है कि तुम पार्टी की बात करते हो। हम सब पार्टी की बात करते हैं---करनी पडती है। न करें, तो राजनीति चल नहीं सकती है। लेकिन कुछ मसले ऐसे भी आते हैं, जिन्हें पार्टीबाजी से ऊपर उठ कर देखना चाहिये। देश को पार्टी के लिये कुर्बान नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस (आई) का सिद्धांत यह है कि देश बचना चाहिये, पार्टी बचे या न बचे। हम देश को पार्टी से ऊपर रखना चाहते है। मेरी प्रार्थना है कि आप भी यही भावना पैदा करें कि अगर कभी पार्टी का का नुकसान होता हो, तो उसको बर्दाशत कर लें, लेकिन देश का नुकसान न हो।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : प्रैजिडेंट्स रूल के बारे में भी सवाल पूछा गया है।

श्री जैल सिंह : मैंने पहले ही कह दिया है कि हम ने प्रैजिडेंट्स रूल के बारे में कोई गौर नहीं किया है।

श्री टी० एस० नेगी (टिहरी गढवाल) : सभापति महोदय, आज सारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र बड़े खतरे में है। मंत्री महोदय के मुताबिक ही विदेशी ताकतें वहां कुछ शोरो-गुल कर रही हैं। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मंत्री महोदय को अब तक यह पता नहीं चला है कि आर्म्ज किस देश से आये हैं, किस रास्ते से आये हैं। इस बात का पता क्यों नहीं चला है कि वे आर्म्ज कहां से आये हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में जो विदेशी ताकतें काम कर रही हैं, उनमें कौन-कौन से देश इनवाल्व्ड हैं और क्यों हैं।

हिन्दुस्तान के इतिहास में इतना बड़ा जन-संहार नहीं हुआ है और फिर मंत्री महोदय ने रिपोर्ट भी दी है कि उसमें 315 व्यक्तियों को जानें गई। लोगों में जो चर्चायें चल रही हैं, उनमें कहा जाता है कि हजारों आदमी मारे गये हैं, लेकिन उसको छिपाया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि जो अच्छे-अच्छे विदेशी हथियारों से लोगों को मारा गया, उसके बारे में मंत्री महोदय क्या राय रखते हैं।

श्री जैल सिंह : चेयरमैन साहब, मेम्बर साहबान की एक बात तो मेरी समझ में नहीं आ सकी। वे बार-बार पूछते हैं कि कौन-कौन सी विदेशी ताकतें दखल दे रही हैं। हमने तो

[श्री जैल सिंह]

यह कहा ही नहीं है कि विदेशी ताकतें दखल दे रही हैं। कुछ मेम्बर कहते है और हम उस पर गौर कर लेते हैं। लेकिन अगर विदेशी ताकतें दखल देंगी, तो क्या वे दिखाई देंगी? वे तो छिपकर ही दखल देंगी। इस लिए मैं यह साफ़ कर देना चाहता हू कि सरकार किसी ताकत पर, किसी विदेशी हुकुमत पर इस बात को दोष नहीं लगाती कि फ़लां हुकूमत हमारे अंदरूनी मामलों में दखल देती है। हमने तो जेनरल बात कही है कि हम किसी भी मुल्क के अन्दरूनी मामलों में दखल नहीं देते हैं। अगर हमारे अन्दरूनी मामलों में कोई दखल देगा, तो हम उसका जवाब मजबूती से देगे और उसमें कोई डील नहीं होगी।

एक माननीय सदस्य: उसका हाथ काट देंगे।

श्री जैल सिंह: हां, यह तो मैंने कह दिया। अगर हाथ दिखाई दिया कि कोई मदाखलत कर रहा है, तो हाथ हो, या पांव हो, कोई भी हो फिर वह काट देंगे।

वह जो उनका शुबहा है कि 315 से ज्यादा मौतें हुई हैं, हो सकता है कि मृत्यू ज्यादा हुई हो या न हुई हो। लेकिन मैंने अपने स्टेटमेंट में पहले यह कह दिया था कि मेरे पास भी कुछ लोग आए, उन्होंने शुबहा प्रकट किया और चिन्ता व्यक्त की कि सी0 एम0 ने जो आपको बताया है उससे ज्यादा मृत्यु हुई है। लेकिन इस बात का तो पता चल जायगा। और बगैर देखे या गिने हुए कैसे जिम्मेदारी से मै कह सकता हूं कि ज्यादा हुई है या नहीं?

SHRI K. P. SINGH DEO (Dhenkanal): In para 4 of the Minister's reply, he has out off the scope for seeking further clarification or getting any query answered. Even then, I would like to ask a few questions.

It is rather shocking that an incident of such a magnitude and intensity should happen, specially when the House was debating for the last three days what was happening in Assam and the entire north-eastern sector; not only that, the writing on the wall was very much clear. It implies that either both the State intelligence and the Central intelligence had failed to do their duties or the authorities, that be, failed to react to the intelligence reports submitted by them. So, my first question would be whether the State or the Central intelligence had any reports to the effect that such a situation was building up and if so, whether any action was taken to forestall that and what was the action taken to forestall that. I hope that the Home Minister would kindly take us into confidence in this.

Secondly, it raises serious doubts, whether, when a situation of such a magnitute as happened, it does not affect the stablity, security and integrity of our country—because such a thing could happen within the boundaries of our country at such a strategic position. I would like to know, keeping the geo-political and geostrategic position in view, and knowing full well the role of certain militant groups which are being funded by the Western countries, which are getting their military and political training from China and which are operating in these very sensitive areas, what are the positive steps now being taken to see that such a thing does not arise.

Thirdly, this vast population which has been affected by this outrage, is in a state of shock. I would like to know what are the relief measures which have been taken or which are being contemplated to be taken to give relief and succour to the shocked population.

श्री जैल सिंह: मेम्बर साहब का यह शक है कि हमारा जासूसी विभाग और स्टेट का गुप्तचर विभाग जो था उसने वक्त पर इत्तिला नहीं दी। एक बात मैंने पहले ही कह दी है कि जहां-जहां भी हमको इस बात की इत्तिला मिलती थी कि एक दूसरे के खिलाफ नफरत का प्रचार हो रहा है और नफरत के प्रचार के नतीजे यही हो सकते हैं कि कुछ लोग जोश में आ कर एक को मारना शुरू करते हैं, दूसरे उसको मारना शुरू करते हैं और गड़बड़ बढ़ जाती है, तो जहां भी ऐसी इत्तिला मिलती थी वहां आवश्यक कदम उठाते रहे हैं। मगर स्टेट गवर्नमेंट जो इयूटी एलेक्टेड गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट का ही देखना फर्ज था कि हमको क्या कहती है जब भी स्टेट गवर्नमेंट ने हमको कहा और जब स्टेट गवर्नमेंट के अलावा हमारे आइ बी की रिपोर्ट हमको मिली तो हमने स्टेट गवर्नमेंट को इत्तिला दी और जब स्टेट गवर्नमेंट ने हम से मदद मांगी तो हमने उनको मदद दी। इसलिए इस बात पर जाना कि गुप्तचर विभाग ने क्यों नहीं इस मामले में बताया कोई माने नहीं रखता।

साथ-साथ यह जो कहा है कि आप बताएं कि यह पश्चिमी ताकतें हैं या पूर्वी ताकतें हैं कौन हैं जो दखल देती हैं, मैं समझता हूं कि नेशन के इंटरेस्ट में यही बात है कि मुझ से कुछ न कहलवाया जाय और मैं समझता हूं कि यह कुछ नहीं कहना चाहिए।

जहां तक रिलीफ का संबंध है, मैंने पहले ही कह दिया है कि रिलीफ वर्क के लिए हम यह भी सोचते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट से जा कर सलाह-मश्विरा करें। यहां से कुछ अफसर जाने हों तो उनको भेज देंगे। साथ ही हम पब्लिक कोआपरेशन भी लेंगे। जो सोशल संस्थाएं हैं, एजूकेशनल संस्थायें हैं, धार्मिक संस्थायें हैं जो भी ऐसी संस्थायें सेवा के लिए तैयार होंगी, इंसानियत की खिदमत के लिए तैयार होंगी उनके सहयोग का लाभ उठाया जायेगा। साथ ही पर्जरी की जो भावना है, नफरत की जो भावना है उसको भी दूर करने के लिए सरकार पूरा यत्न करेगी।

MR. CHAIRMAN: Now the House stands adjourned to meet again at 11 a.m. tomorrow.

18.11 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, June 13, 1980/Jyaistha 23, 1902 (Saka).

GMGIPMRND—SI—441 LS—JC 791—29-7-80—882